सीमा पर निगरानी से हमले तक, सेना की नई ताकत बनेगा दिव्यास्त्र एमके-1

- स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का जोधपुर में युद्ध स्तरीय परिस्थिति में कई सटीक परीक्षण किए गए
- अब तक निगरानी और हमले के लिए अलग-अलग प्रणालियों पर थी निर्भरता, नया सिस्टम दोनों काम साथ करेगा
- एआइ और सेंसर से लैस ड्रोन मोबाइल लांचर से तुरंत छोड़ा जा सकता है, दिन-रात दे सकता है रियल-टाइम जानकारी

400 किमी प्रति घंटे की गति से 500 किमी तक पांच घंटे तक उड़ान भर सकता है ड्रोन

15 किलो तक का बम भी ले जा सकता है, सटीक निशाना लगाने तक लंबे समय तक मंडरा सकता है

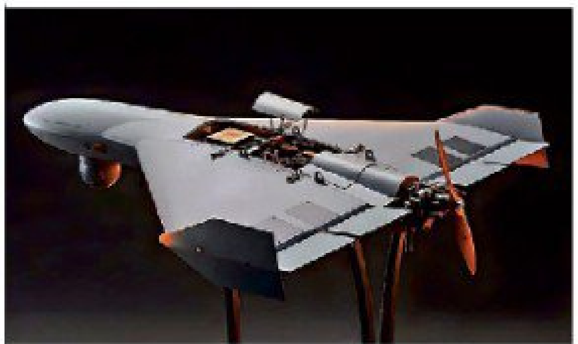

'दिव्यास्त्र एमके-1' लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन। इंटरनेट मीडिया

एएनआइ, नई दिल्ली : भारतीय सेना सीमा पर निगरानी और दुश्मन पर सटीक कार्रवाई की अपनी क्षमता को लगातार मजबूत कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरित के 'दिव्यास्त्र एमके-1' लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन के सफल परीक्षण के रूप में सामने आया है। अब तक सेना को कई परिस्थितियों में खुफिया जानकारी जुटाने, घुसपैठ पर नजर रखने और लक्ष्य पर हमला करने के लिए अलग अलग संसाधनों का सहारा लेना पड़ता था। दिव्यास्त्र एमके-1 इन सभी क्षमताओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।

आपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका-ईरान युद्ध में लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन की सफलता को देखते हुए भारतीय सेना का ज्यादा जोर इस तरह की रक्षा प्रणाली पर है। इसके अलावा सेना विदेशी तकनीक पर आधारित महंगे ड्रोन की बजाय किफायती स्वदेशी ड्रोन को भी बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में जोधपुर में इस ड्रोन ने युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और आधुनिक सेंसरों से लैस यह प्रणाली दिन और रात दोनों समय रियल-टाइम में जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंचा सकती है। इससे सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घुसपैठ की कोशिश का पता पहले से कहीं अधिक तेजी और सटीकता से लगाया जा सकेगा। दिव्यास्त्र एमके-1 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर यह अपने साथ 15 किलोग्राम तक का वारहेड ले जाकर लक्ष्य पर सटीक हमला भी कर सकता है। लक्ष्य की पहचान होने तक यह लंबे समय तक हवा में मंडरा सकता है और सही अवसर मिलने पर कार्रवाई कर सकता है। इसी वजह से इसे 'लोइटरिंग म्यूनिशन' श्रेणी का ड्रोन भी कहा जाता है। करीब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने वाला यह ड्रोन लगातार पांच घंटे तक हवा में रह सकता है और लगभग 500 किलोमीटर तक के क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। एलओसी, एलएसी, रेगिस्तानी इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों और घने जंगलों जैसे कठिन भूभागों में भी इसका उपयोग प्रभावी माना जा रहा है।

बहुत कम समय में उड़ान भरता है दिव्यास्त्र एमके-1 ड्रोन पेज>>6

'पीएम स्वनिधि' से अनगिनत रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन बदला : मोदी

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि रेहड़ी और पटरी वालों का समर्थन करने वाली पीएम स्वनिधि योजना ने अनगिनत स्ट्रीट वेंडरों के जीवन को बदल दिया है, क्योंकि इसने उन्हें बिना सिक्योरिटी मिले ऋण, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित की है। योजना के छह साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि विश्वास, गरिमा, सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक योगदान का प्रतीक है।

कोविड महामारी के दौरान जून, 2020 में शुरू की गई इस योजना को सरकार ने 2030 तक बढ़ा दिया है। इसमें 7,332 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट और उच्च ऋण सीमाएं शामिल हैं। इसका लक्ष्य 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच बनाना और यूपीआइ-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड जैसे प्रोत्साहनों से आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देना है।

पीएम मोदी ने एक पोस्ट में कहा, "आज हम पीएम स्वनिधि के छह वर्षों का जश्न मना रहे हैं। एक योजना जिसने अनगिनत रेहड़ी और पटरी वालों की जिंदगी को बदल दिया है, जिससे उन्हें बिना किसी पूंजी या संपत्ति को गिरवी रखे ही ऋण मिल जाता है। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन और विकास के नए अवसर मिले हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी शुभकामनाएं सभी लाभार्थियों को जिनकी दृढ़ता और उद्यमिता हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है।" सरकार के अनुसार, पीएम स्वनिधि से भारत में लगभग 95 प्रतिशत लाभार्थियों ने पहली बार औपचारिक संस्थागत ऋण प्राप्त किया, जबकि 30 प्रतिशत ने पीएम स्वनिधि के ऋण से आगे बढ़कर अतिरिक्त ऋण प्राप्त किया। पीएम स्वनिधि ने लगभग 20 प्रतिशत वार्षिक आय वृद्धि में योगदान दिया। केंद्र ने कहा कि 800 करोड़ रुपये रेहड़ी-पटरी वालों को कैशबैक प्रोत्साहनों और ब्याज सब्सिडी से पहुंचे, जिससे डिजिटल भुगतान को और अधिक लाभकारी बनाया गया और मजबूत वित्तीय आदतें विकसित की गईं। 75 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों ने 112 लाख से अधिक ऋण प्राप्त किए, जिनकी कुल राशि 17,800 करोड़ रुपये से अधिक है। सरकार ने कहा, "841 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन के साथ स्ट्रीट वेंडर तेजी से विकसित हो रहे।"

- **पीएम बोले-छह वर्षों में 95 प्रतिशत लाभार्थियों को पहली बार संस्थागत ऋण मिला**
- **सरकार ने 2030 तक योजना बढ़ाई, इसमें 7,332 करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट**

नरेन्द्र मोदी। फाइल

प्रो. एम एल मीणा

भूगोल विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

आजकल

बदलती व्यवस्था में भारत के लिए अवसर

वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था को यदि एक वाक्य में समझना हो तो यह कहना पर्याप्त होगा कि दुनिया अब मुक्त व्यापार से अधिक सुरक्षित व्यापार पर भरोसा करने लगी है। पिछले तीन दशकों तक परस्पर निर्भरता और नवीन आर्थिकी का मूल सिद्धांत यह था कि उत्पादन वहीं होगा, जहां लागत सबसे कम होगी और मांग ज्यादा हो, भले ही राजनीतिक जोखिम बड़ा क्यों न हो। परंतु कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-ईरान टकराव और अमेरिका-चीन तकनीकी संघर्ष ने इस सोच को उलट दिया है। ऐसे में भारत के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं

विनिर्माण केंद्र के रूप में स्वयं को आगे बढ़ाने की भारत में व्यापक क्षमता है। फाइल

भारत आज एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लिहाजा दुनिया उसे आर्थिक संभावना से अधिक अब भूराजनीतिक शक्ति के रूप में देखने लगी है। यही परिवर्तन निर्णायक है। वर्ष 1991 के बाद भारत को उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, जबकि आज भारत वैश्विक आर्थिक संरचना का स्थायी हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस संदर्भ में भारत के उभार को केवल राष्ट्रवादी उत्साह के चश्मे से देखना सिर्फ एक पक्ष होगा। वस्तुतः भारत आज जिस स्थान पर दिखाई दे रहा है, वह केवल उसकी उपलब्धियों का परिणाम भर नहीं है। वह वैश्विक अस्थिरता की उपज भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया भारत की ओर उतनी नहीं बढ़ी, जितनी वह चीन पर अत्यधिक निर्भरता से पीछे हटी है। यही कारण है कि भारतीय अवसर को समझने के लिए पहले हमें चीन की थकान को समझना चाहिए।

पिछले कुछ वर्षों में चीन के प्रति पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण तेजी से बदला है। कभी जिसे विश्व की फैक्ट्री कहा जाता था, वही चीन अब रणनीतिक जोखिम के रूप में अधिक देखा जा रहा है। भले ही इसे देखने का परिप्रेक्ष्य परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग हैं। लेकिन हालिया भू-राजनीतिक बदलावों को देखें तो पाते हैं कि अमेरिकी कंपनियों पर घरेलू दबाव बढ़ रहा है कि वे अपनी उत्पादन इकाइयों को चीन से बाहर निकालें। ऐसे में भारत, वियतनाम, मेक्सिको और इंडोनेशिया जैसे देशों को बड़ा अवसर मिला है।

हालांकि यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि भारत चीन का वास्तविक विकल्प बन चुका है, जैसा कि आज के समय में प्रचलित है। चीन आज भी वैश्विक विनिर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। उसकी लाजिस्टिक क्षमता, बंदरगाह संरचना, तकनीकी दक्षता और निर्यात नेटवर्क भारत से कहीं आगे हैं। जैसे कि भारत में अभी भी लाजिस्टिक लागत जीडीपी के 13-14 प्रतिशत तक पहुंच जाती है, जबकि चीन में यह काफी कम है। यही कारण रहता है कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश तो कर रही हैं, लेकिन अपनी मुख्य उत्पादन क्षमता अब भी चीन में बनाए हुए हैं।

फिर भी भारत को लेकर वैश्विक उत्साह के पीछे बड़ी आर्थिक संभावना मौजूद है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बनी हुई है। लेकिन यहां असली सवाल यह नहीं कि भारत कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि भारत किस प्रकार का विकास माडल बना रहा है। क्योंकि अक्सर आंकड़ों की चमक वास्तविक संरचनात्मक समस्याओं को ढक देती रही है। इसका अर्थ यह है कि भारत मात्रात्मक अर्थव्यवस्था तो बन रहा है, लेकिन अभी समग्र गुणात्मक विकास से दूर है। इतिहास बताता है कि केवल विकास दर किसी राष्ट्र को स्थायी शक्ति नहीं बनाती हैं। यदि आर्थिक वृद्धि, रोजगार और सामाजिक समरसता न हो, तो वही विकास अंततः राजनीतिक व आर्थिक असंतोष का कारण बन सकता है।

यहीं भारत के सामने एक अलग प्रकार की चुनौती सामने आती है कि क्या भारत उत्पादक जनसंख्या तैयार कर रहा है? आज दुनिया भारत को उसकी युवा आबादी के कारण अवसर के रूप में तो देख रही है। लेकिन यह जनसांख्यिकीय लाभ तभी शक्ति बनेगा, जब भारत अपनी शिक्षा और कौशल व्यवस्था को वैश्विक उद्योग की जरूरतों के अनुसार बदल सके।

वस्तुतः भारत की आर्थिक कहानी को समझने के लिए हमें उसकी विदेश नीति को भी आर्थिक दृष्टि से देखना होगा। काफी समय से भारत ने जिस प्रकार बहुध्रुवीय कूटनीति अपनाई है, वह भू-राजनीतिक रणनीति के साथ आर्थिक सुरक्षा का हिस्सा भी है। लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ भारत के संबंध थोड़े आशंकित हैं, क्योंकि यह संबंध उन परंपरागत और विरासत की कीमत पर बने हैं, जिन्होंने भारत के साथ मित्रवत व्यवहार रखा।

इसके अलावा, हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि भारत की आर्थिक संरचना अभी भी कई बाहरी निर्भरताओं से घिरी हुई है। ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता से कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ी सी हलचल सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन भारत की विकास यात्रा के लिए नया संकट बनता जा रहा है। इसलिए आने वाले वर्षों में वैश्विक भू-आर्थिक परिदृश्य में भारत को ग्रीन ग्रोथ और विकास के बीच कठिन संतुलन बनाना होगा।

अंततः दुनिया के नए भू आर्थिक नक्शे में भारत निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत 21वीं सदी का नया आर्थिक केंद्र बन चुका है। फिलहाल भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां अवसर और भ्रम दोनों साथ-साथ मौजूद हैं। यदि भारत विनिर्माण, रोजगार, तकनीक और सामाजिक समानता के बीच संतुलन बना पाया तो संभव है कि आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था का केंद्र वास्तव में एशिया और विशेष रूप से भारत की ओर खिसक जाए। लेकिन यदि विकास केवल आंकड़ों और नारों तक सीमित रहा, तो भारत भी उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिन्होंने संभावना तो दिखाई, परंतु संरचनात्मक बदलाव पूरा नहीं कर पाए। दुनिया का भू-आर्थिक नक्शा तेजी से बदल रहा है। भौगोलिक नजरिये से आर्थिक संभावना को देखें तो इतिहास प्रायः अवसर देता है, लेकिन वह किसी राष्ट्र को स्थायी महत्व तभी देता है जब वह अवसर को संस्थागत शक्ति में बदल सके।

विश्व व्यवस्था के प्रारूप में परिवर्तन

रवि दास बिश्नोई

अध्येता, इंडो-पैसिफिक डोमेन

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्मित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दशकों तक नियम-आधारित वैश्विक प्रणाली की आधारशिला बनी रही थी। किंतु आज उस व्यवस्था की बुनियाद पहले जैसी मजबूत दिखाई नहीं देती है। ब्रेटन वुड्स संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ, नाटो और डालर-आधारित वित्तीय तंत्र को लेकर चल रहे हालिया विमर्श इसके स्पष्ट संकेतक हैं। वर्ल्ड इकोनमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 में पहली बार भू-आर्थिक टकराव को दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम बताया गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि आने वाले दशक में दुनिया एक बहुध्रुवीय अथवा अधिक विखंडित व्यवस्था की ओर बढ़ेगी। ऐसे में प्रश्न केवल यह नहीं रह जाता कि पुरानी व्यवस्था टूट रही है या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या उसकी जगह कोई नई व्यवस्था आकार ले रही है या फिर हम एक स्थायी वैश्विक अव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं।

दरअसल, वैश्विक प्रतिस्पर्धा अब चोकप्वाइंट भू-राजनीति का रूप लेती जा रही है, जहां सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, ऊर्जा गलियारे और समुद्री मार्ग नई शक्ति-स्पर्धा के केंद्र बन चुके हैं। चीन ने अमेरिकी टैरिफों के जवाब में प्रतिशुल्क लगाए, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच अमेरिका के चीन को निर्यात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। वहीं वियतनाम और कंबोडिया जैसे आसियान देश, जिनका अमेरिका के साथ लगभग 227 अरब डालर का व्यापार अधिशेष है, 49 प्रतिशत तक के संभावित टैरिफ दबाव की चपेट में आ गए। इन घटनाओं ने वैश्विक मूल्य-शृंखलाओं के पुनर्गठन की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। यदि वर्तमान भू-आर्थिक युग की सबसे तीखी प्रतिस्पर्धा को पहचानना हो, तो वह शायद मुद्रा और वित्तीय शक्ति के क्षेत्र में दिखाई देती है। ब्रिक्स समूह अब डालर-केंद्रित वित्तीय व्यवस्था को चुनौती देता दिख रहा है। रूस और ईरान वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों की खोज में हैं, जबकि ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

इस समूचे परिदृश्य में यह समझना भी आवश्यक है कि उभरती हुई विश्व व्यवस्था का स्वरूप कैसा हो सकता है। अमेरिका और चीन के संबंधों को देखें तो वे प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचते हुए अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को मजबूत करने की रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। लिहाजा एक ऐसी व्यवस्था उभर रही है जिसमें नए नियम गढ़ने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उन नियमों का अंतिम स्वरूप अभी अस्पष्ट है। भारत इस बदलती व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थिति रखता है। वह ब्रिक्स का सदस्य भी है, क्वाड का भागीदार भी है और साथ ही डब्ल्यूटीओ में बहुपक्षवाद का समर्थक भी बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने अपेक्षाकृत संयत कूटनीति अपनाने का प्रयास किया है, जिसके कारण मशीनरी और वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों में उसे अवसर भी प्राप्त हुए हैं। किंतु इसके साथ-साथ भारत को डब्ल्यूटीओ जैसे मंचों पर संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के विरुद्ध अपनी आवाज भी निरंतर उठानी होगी।

विश्व व्यवस्था का अगला चरण संभवतः न तो अमेरिकी एकध्रुवीयता पर आधारित होगा और न ही पूर्ण चीनी वर्चस्व पर होगा। इसके बजाय यह एक बदलते संतुलनों वाली व्यवस्था होगी, जहां आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक शक्ति एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी होंगी। इस बीच एक बात दिखाई देती है कि आने वाले समय में वही राष्ट्र अधिक प्रभावशाली होंगे जो अपनी आर्थिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और कूटनीतिक शक्ति को अपने भूगोल के अनुरूप प्रभावी ढंग से संयोजित कर सकेंगे।

सीएम ने समाज कल्याण की समीक्षा की, कहा-कुपोषण मिटाने में सीएसआर की मदद लें

बुज़ुर्ग, विधवा व दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते, बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेडलाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात कही। बोले-हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों के बैंक खातों में पेंशन के रुपए जरूर पहुंच जाएं। इसकी गारंटी हो।

मुख्यमंत्री ने विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास की आईसीडीएस, सामाजिक सुरक्षा और महिला विकास निगम की रिपोर्ट देखने के बाद कई अहम निर्देश दिए। कहा बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि के पेंशन में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बच्चों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का सहारा लें। तकनीक से मॉनीटरिंग हो। विभाग में जितने भी पद खाली हैं, उन्हें तुरंत भरने के लिए मिशन मोड में काम हो। अनाथ और असहाय बच्चों के लिए चल रही परवरिश योजना तथा अन्य कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाएं।

बैठक और मुख्यमंत्री के कड़े रुख के कई मायने रहे

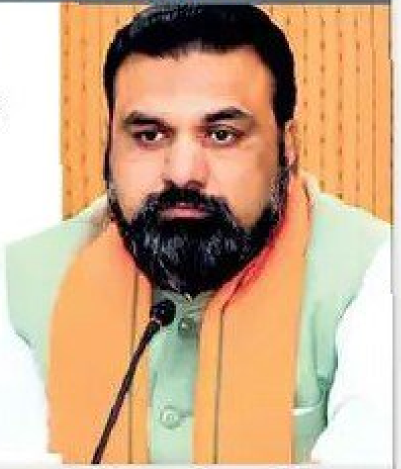

- **कमजोर और वंचित वर्ग पर फोकस :** समाज कल्याण विभाग की योजनाएं सीधे तौर पर समाज के सबसे निचले पायदान के लोगों (महादलित, अति पिछड़ा, महिलाएं और बच्चे) से जुड़ी हैं। इन योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता, सीधे सरकार की छवि चमकाती है।
- **चुस्त-दुरुस्त मॉनिटरिंग :** बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा 'गहन निगरानी' और 'पारदर्शिता' शब्द का बार-बार इस्तेमाल यह बताता है कि अब सरकार योजनाओं की केवल घोषणा करके शांत नहीं बैठने वाली। ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए रैंडम डिजिटल चेकिंग की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि, आगे के दिनों में इन सबकी परख होगी।

भास्कर एनालिसिस कुपोषण के खिलाफ 'कॉरपोरेट' सहयोग

बिहार में स्टंटिंग (उम्र के हिसाब से कम लंबाई) और वेस्टिंग (लंबाई के हिसाब से कम वजन) के आंकड़े शुरू से सरकार के लिए सिरदर्द रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों से एक इनोवेटिव आइडिया पर काम करने को कहा। यह कि आंगनबाड़ी केंद्रों की और बेहतरी के लिए सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड का इस्तेमाल हो। इसकी संभावना देखें। ऐसा करें।

क्या है पीछे की रणनीति?

बिहार सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के 'खिचड़ी वितरण केंद्र' वाले मौजूदा स्वरूप या धारणा को बदलना चाहती है। इसे 'स्मार्ट प्ले स्कूल' के रूप में विकसित करना चाहती है। सरकारी बजट से इतर, देश की बड़ी कंपनियों के सीएसआर फंड को सीधे आंगनबाड़ी केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की बात है।

Industrial output slows to 4.9% in new data series

The base year has been revised to 2022-23 from 2011-12; growth rate in April was slower than 5.8% recorded in the corresponding period last year; mining and quarrying output declined by over 5%

Ashokamithran T.
MUMBAI

India's industrial output, as measured by the Index of Industrial Production (IIP), grew 4.9% in April 2026 under the revised series with 2022-23 as the base year released on Monday. The growth rate was slower than 5.8% recorded in April last year with 2011-12 as the base year.

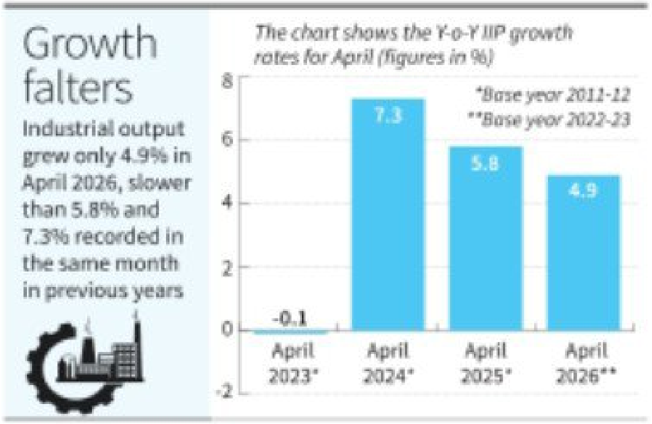

The new series has broadened the coverage of the index by incorporating water supply, sewerage and waste management activities and gas supply, while retaining the existing three core sectors – mining, manufacturing, and electricity. Of the four sectoral indices, three grew at a slower pace and one shrunk in the reporting month on a year-on-year basis. While mining and quarrying output declined by over 5.1%, manufacturing sector output grew at 6.2% in the reporting month, slightly slower than the 6.3% in 2025. The electricity and gas supply sector grew at 4.9% while water supply, sewerage and waste management grew at 6.6%.

The base years of major macroeconomic indicators, which were earlier 2011-12, were revised in 2026 beginning with the GDP. The IIP is the latest in the measures that have been revised to 2022-23 as the base year.

Besides adding new sectoral divisions, the new series also entails "improved granularity". For instance, mining sector index will now include data classification for fuel minerals, metallic minerals, including rare earth minerals and non-metallic minerals, including minor minerals. Similarly, the electricity index has been classified into renewable and non-renewable sources.

The new basket of goods to calculate IIP consists of 1,042 products mapped to 463 item groups. The older series had just 839 items mapped to 407 item groups. Further, the weights provided to each sector and each industry within the manufacturing sector has been revised in line with the updated Gross Value Added (GVA) 2022-23 series.

CONTINUED ON
» PAGE 10

'No space for anti-India elements in Myanmar'

Promising talks: PM Narendra Modi with Myanmar President Min Aung Hlaing in New Delhi on Monday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Visiting Myanmar President Min Aung Hlaing has assured India that he will not allow use of his country's territory by groups that pose a security threat to Indian interests. The concern was raised by Prime Minister Narendra Modi, who held broad-spectrum conversations with Mr. Hlaing on Monday, including calls for dialogue between the junta-backed government and the pro-democracy Opposition in Myanmar. Foreign Secretary Vikram Misri said the discussion included the issue of detention of former leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi.

"The President reiterated Myanmar's assurance that its territory would not be permitted to be used against India's security interests. The Prime Minister affirmed that India... remained committed to deepening security cooperation," a joint statement issued at the end of the official discussion mentioned.

CONTINUED ON
» PAGE 10

IMEC is caught between commerce and geopolitics

Rajeev Agarwal

Retired colonel, a Senior Research Consultant at CRF, Delhi, and the author of 'Between Tehran and Tel Aviv – Gaza's Story of Unending War'

The ongoing war in Iran has shattered many myths and brought to light realities that expose the structural vulnerabilities of the existing world order. Iran, which was no match for the combined military might and technological superiority of Israel and the United States, has not only withstood the military onslaught but has also retaliated in ways that were neither expected nor planned for. Nearly three months into the conflict, although a fragile ceasefire is holding, there appears to be no immediate solution to end the war or achieve the politico-military objectives that Israel and the U.S. set at its outset. While Iran has suffered major losses to its leadership, infrastructure and military assets, the American military has also incurred unprecedented losses.

Lessons from the Iran conflict

A recent U.S. Congressional Research Service report has noted that 42 U.S. aircraft have been lost or damaged so far during "Operation Epic Fury" – the war with Iran – which includes fifth generation stealth fighters such as the F-35. Plus, the ability to intercept Iranian missiles and drones has been severely degraded as more than half the total inventory of Patriot, Tomahawk and Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) missiles have been expended. With more than 240 American targets reportedly hit by Iran, the conflict has shattered the myth that military superiority alone will guarantee an outright victory. Several of the asymmetric tactics employed by Iran have caught the U.S. and Israel on the back foot.

Another reality check underscored by this war is the critical importance of global choke points and how their blockade can severely disrupt the global economy. Iran, by imposing a blockade on the Strait of Hormuz early in the conflict, has virtually brought the global economy to its knees. Nearly 20 million barrels of crude oil, accounting for about a third of global oil supplies, pass through this narrow sea passage every day. India is among the countries most affected, as it imports nearly 88% of its crude oil requirements, amounting to about 1.8 billion barrels annually. While the world grapples with the blockade and works to diversify its energy sources, one thing is clear: there is an urgent need to explore and develop alternative connectivity options beyond existing trade routes, particularly maritime routes. New routes and corridors must be developed that avoid the two 'C's – conflict zones and choke points.

However, this realisation is neither new nor have countries been idle in pursuing solutions. Transnational connectivity projects such as the International North-South Transport Corridor (INSTC) and the Belt and Road Initiative (BRI) were conceived precisely for this purpose. The INSTC was designed to bypass the Suez Canal choke point, while the overland component of the BRI across Asia and Europe seeks to reduce dependence on both the Malacca Strait and the Suez Canal. Another major connectivity project is the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC). Unlike the other initiatives, IMEC traverses parts of West Asia, a region that has been significantly affected by the current conflict.

The Iran conflict strengthens the case for the India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) while simultaneously complicating its execution

The IMEC framework

What is IMEC? The IMEC is a transformative and ambitious connectivity initiative that was officially announced at the G-20 Summit in New Delhi in September 2023. It seeks to connect India with Europe across the Arabian Peninsula, bypassing the traditional choke point of the Suez Canal. The project envisions a multimodal economic corridor integrating railways, ports, highways, energy networks and digital infrastructure to enhance trade, investment and connectivity. Unlike conventional transport corridors, IMEC is conceived as a holistic and multidimensional infrastructure project encompassing sea routes, rail networks, pipelines, undersea high-speed data links, green hydrogen corridors and transnational energy transmission grids.

The proposed structure has three distinct sections. The eastern section links India with West Asia through sealinks to the United Arab Emirates (UAE). The central section consists of an overland route across West Asia, traversing the UAE, Saudi Arabia, Jordan and Israel, and culminating at the port of Haifa on Israel's Mediterranean coast. The western leg of the corridor is sea-based, connecting Haifa to various European ports, beyond which the continent's extensive transportation network takes over.

What has happened due to the war? Soon after IMEC was announced, the war in Gaza broke out on October 7, 2023, placing the project on the back burner. Major areas of the originally envisioned corridor, particularly those involving Israel and the port of Haifa, were directly affected by the conflict.

Soon after the Iran-Israel '12-Day War' in June 2025, there was a concerted effort to move the project forward. However, the ongoing conflict involving Iran has once again thrown a spanner into its execution. Key ports in the UAE, particularly Jebel Ali and Fujairah, have been repeatedly targeted by Iran, while disruptions in the Strait of Hormuz have exposed the geographical vulnerabilities of these ports.

Another critical fault line exposed by the war is the deep faultlines and divergence in the positions adopted by Saudi Arabia and the UAE in the war. Both countries are key partners in IMEC, and any adversarial posture between them could prove to be a major setback for the corridor, whose success depends on smooth coordination and seamless connectivity across the region. The UAE's April 2026 announcement that it was opting out of the global oil grouping, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) and reports of its growing strategic coordination with Israel, including the deployment of Israeli defence systems such as the Iron Beam, risk widening differences between Riyadh and Abu Dhabi. Such developments are unlikely to augur well for either regional stability or the future of IMEC.

Navigating the challenges

The war in Iran has highlighted two important issues for both West Asia and IMEC. First, there is an urgent need for projects such as IMEC that can bypass conflict zones and choke points. However, for such initiatives to succeed, they must also navigate the region's geopolitical complexities, including the rapidly evolving dynamics among key partners such as Saudi Arabia and the UAE.

To address the first challenge, IMEC must evolve into a broader and more flexible framework while keeping open the possibility of reverting to the originally envisioned alignment once the conflict subsides. To this end, the option of developing key ports in Oman – such as Salalah, Duqm and Muscat – as eastern entry points could be explored, as they are located well away from the conflict-prone Strait of Hormuz. Similarly, on the western end, until the port of Haifa becomes a secure transit hub, a western spur passing through Egypt and terminating at one of its major Mediterranean ports could offer a viable alternative. Egypt already possesses the logistics ecosystem required to support IMEC, including the Suez Canal Economic Zone, six operational ports and four industrial zones specialising in green hydrogen, liquefied natural gas, shipbuilding and other future-oriented sectors.

To address the second challenge, countries such as India, which enjoy close relations and the trust of both Saudi Arabia and the UAE, will have to navigate a delicate but critical diplomatic terrain. European countries such as Italy and France, which are positioning themselves as key champions of IMEC in Europe, will also need to play an active role. The growing recognition of IMEC's strategic importance was evident during Prime Minister Narendra Modi's visit to Europe in May 2026. While elevating their bilateral ties to a Special Strategic Partnership, India and Italy reaffirmed their commitment to cooperate on IMEC, recognising its transformative potential to reshape and promote global trade, connectivity and prosperity.

The bottom line is clear. The war in Iran has underscored the need for transnational connectivity projects such as IMEC that can bypass conflict zones and strategic choke points. However, for such initiatives to succeed, they must overcome the geopolitical complexities in West Asia.